

Padma Shri



SHRI C.S. VAIDYANATHAN

Shri C.S. Vaidyanathan is a Senior Advocate practicing in the Supreme Court of India, various High Courts across the country, various Tribunals (Inter-State River Water Disputes, Telecom, Electricity/ Power, Companies, Environment, Arbitral Tribunals (International and Domestic), Consumer Disputes, etc.), etc. for more than 50 years.

2. Born on 8th August, 1949 in Coimbatore, Tamil Nadu, Shri Vaidyanathan did his Bachelors in Science from St. Joseph's College, Bengaluru and completed his Bachelors in Law from Madras Law College, Chennai before he was 20. He then did his Masters in Social Work from National Institute of Social Sciences, Bangalore. He joined DCM Ltd. as a Management Trainee and worked there for four years. He joined the Law Chamber of Shri M.K. Nambyar, Senior Advocate and Shri K.K. Venugopal, Former Attorney General for India and Senior Advocate in June, 1974 and shifted his legal practice to the Supreme Court of India in 1979. He became an Advocate-on-Record in the Supreme Court of India in 1979 and a Senior Advocate in 1992. He was appointed as the First Additional Solicitor General of India in 1998 where he represented the Government of India in numerous sensitive and important matters. He returned to private practise in late 1999.

3. Shri Vaidyanathan has contributed to the socio-political-economic and legal landscape of India by appearing in some of the most significant cases/disputes pertaining to Constitutional Law, Human Rights Law, Religious/Personal Law, Administrative Law, Civil Law, Commercial Law, Taxation Law (Direct and Indirect), Arbitration Law, Property Law, Telecom Law, Intellectual Property Rights (Patents, Copyrights, Trademarks, etc.), Electricity Law, Inter-State River Water Disputes (Cauvery, Ravi-Beas, Narmada, Vamsadhara and Krishna Rivers), Environmental Law, Service Law, Labour Law, Election Law, Infrastructure sector, Regulatory sector, Mines and Minerals Law, Competition Law, Insolvency Law, etc. *Some of the more notable cases in which Shri Vaidyanathan appeared include the Ram Janma Bhumi, Ayodhya Case (Appeared for Ram Lalla), the Justice Verma Commission and Commission of Enquiry on Rajiv Gandhi Assassination (Appeared for Tamil Nadu Police).*

4. Shri Vaidyanathan, has always had a great interest in the sensitive and compassionate side of life such as Community, Education, Arts, Culture, Music, Dance, etc. It is thus, that he is and has been the President, Chief Patron, Trustee, Advisor, etc. of several Educational, Arts, Culture, Music, Dance, Community, Lawyers, etc. Institutions/ Organisations including Bharatiya Vidya Bhawan, Gandharva Mahavidyalaya, Shanmugananda Sangeeta Sabha, Gayatri Fine Arts, SOS Children's Villages, etc. For his fellow legal community, Shri Vaidyanathan is and has been representing their interests and concerns as the Conseiller de President (Advisor to President) and Regional Secretary (South Asia) of UIA- International Association of Lawyers, Vice President of the Bar Association of India, etc.



श्री सी.एस. वैद्यनाथन

श्री सी.एस. वैद्यनाथन एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों से भारत के उच्चतम न्यायालय, देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों, विभिन्न न्यायाधिकरणों (अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, दूरसंचार, विद्युत/ऊर्जा कंपनियों, पर्यावरण, मध्यस्थ न्यायाधिकरण (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू), उपभोक्ता विवाद, आदि) आदि में प्रैक्टिस की है।

2. 8 अगस्त, 1949 को कोयंबटूर, तमिलनाडु में जन्मे, श्री वैद्यनाथन ने सेंट जोसेफ कॉलेज, बंगलुरु से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 20 वर्ष की उम्र से पहले मद्रास लॉ कॉलेज, चेन्नई से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंगलुरु से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर किया। वह एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में डीसीएम लिमिटेड में शामिल हुए और वहां चार वर्षों तक कार्य किया। वह जून 1974 में श्री एम. के. नाम्बियार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. वेणुगोपाल के लॉ कानूनी चेम्बर में शामिल हुए और वर्ष 1979 में उन्होंने अपने कानूनी पेशे को भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। वे वर्ष 1979 में भारत के उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बने और वर्ष 1992 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने। उनको वर्ष 1998 में भारत के प्रथम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1999 के अंत में वे निजी प्रैक्टिस में लौट आए।

3. श्री वैद्यनाथन ने संवैधानिक कानून, मानवाधिकार कानून, धार्मिक/व्यक्तिगत कानून, प्रशासनिक कानून, सिविल कानून, वाणिज्यिक कानून, कराधान कानून (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), मध्यस्थता कानून, संपत्ति कानून, दूरसंचार कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आदि), विद्युत कानून, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (कावेरी, रावी-व्यास, नर्मदा, वंशधारा और कृष्णा नदियाँ), पर्यावरण कानून, सेवा कानून, श्रम कानून, चुनाव कानून, अवसंरचना क्षेत्र, नियामक क्षेत्र, खान और खनिज कानून, प्रतिस्पर्धा कानून, दिवालियापन कानून आदि से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण मामलों/विवादों में पेश होकर (तमिलनाडु पुलिस की ओर से पेश हुए) भारत के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक और कानूनी परिदृश्य में अपना योगदान दिया है।

4. श्री वैद्यनाथन को हमेशा से ही जीवन के संवेदनशील और दयालु पक्षों जैसे कि समुदाय, शिक्षा, कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य इत्यादि में गहरी रुचि रही है। यही कारण है कि वे कई शैक्षिक, कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, समुदाय, अधिवक्ताओं इत्यादि संस्थाओं/संगठनों के अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक, ट्रस्टी, सलाहकार आदि रहे हैं, जिनमें भारतीय विद्या भवन, गंधर्व महाविद्यालय, षण्मुगानंद संगीत सभा, गायत्री ललित कला, एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज इत्यादि शामिल हैं। अपने साथी विधायी समुदाय के लिए, श्री वैद्यनाथन यूआईई- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के काउंसलरडी प्रेसिडेंट (राष्ट्रपति के सलाहकार) और क्षेत्रीय सचिव (दक्षिण एशिया), बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष इत्यादि के रूप में उनके हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।